संवैधानिक व्यवस्था का संकट

Chapter 6

Crisis at the Constitution Order

Q.1 1975 मे आपातकाल की घोषणा के कोई चार परिणाम लिखिए

Ans आपातकाल की घोषणा के चार परिणाम है

(1) सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है

(2) सामाजिक और साम्प्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (R.S.S) और जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया

(3) नागरिकों के विभिन्न अधिकार निष्प्रभावी हो गए अब उनके पास यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

(4) सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी का प्रयोग करके कई गिरफ्तारियाँ की

Q.2 मूल ढाँचे का सिद्धान्त क्या है व्याख्या कीजिए।

Ans भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के "मूल ढांचे" की संरचना को मजबूत बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय संसद के कई मामलों मे निर्देश देता है, 24 वें संविधान संशोधन ने संसद को संविधान मे संशोधन करने का अधिकार दिया। इस मामले को दोबारा 1973 मे केशवानन्द भारती मामले मे उठाया गया।

(i) संसद को संविधान के मूल ढांचे मे संशोधन या उसका उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है।

(ii) संसद को संविधान के किसी भाग मे संशोधन करने का अधिकार है।

(iii) न्यायालय को यह फैसला लेने का अंतिम अधिकार प्राप्त होगा कि कहीं वह संशोधन मूल ढांचे संशोधन तो नहीं कर रहा है

मूल ढाँचे का सिद्धान्त भारतीय संविधान की नींव का पत्थर बन गया। इस सिद्धान्त मे साफ कर दिया गया है कि हमारे संविधान मे कुछ प्रावधान प्रकृति मे मूल है और उन्हे कभी बदला नहीं जा सकता है जबकि बाकी सभी प्रावधान संशोधन की दृष्टि से लचीले है मूल ढाँचे का सिद्धान्त न्यायालय संसदीय व्याख्या के लिए भी नींव का पत्थर साबित हुआ है। क्योकि पिछले तीन दशको मे इसे व्यापक जनसहमति प्राप्त हुई है।